इक्कीसवीं सदी के इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग में सूचना प्रौद्योगिकी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने संपूर्ण मानव जाति की जीवनशैली और संचार प्रणालियों में एक अभूतपूर्व एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किया गया था जिसका मुख्य और परम उद्देश्य देश की 1.43 अरब जनसंख्या को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सशक्त बनाना और सरकारी सेवाओं को सीधे आम जनता के मोबाइल फोन तक सुगमता से पहुँचाना था। आज हम अत्यंत गर्व से यह बात कह सकते हैं कि डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण में हमारा राष्ट्र विश्व के कई विकसित और शक्तिशाली देशों को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। आधार कार्ड परियोजना के अंतर्गत आज 130 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिकों की बायोमेट्रिक पहचान सुरक्षित रूप से दर्ज की जा चुकी है जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी कल्याणकारी योजनाओं का सबसे मजबूत आधार स्तंभ बन गई है। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी और आज 50 करोड़ से अधिक ग्रामीण एवं गरीब तबके के लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे आर्थिक सब्सिडी की राशि जमा हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित यूपीआई प्रणाली आज इतनी अधिक लोकप्रिय हो चुकी है कि प्रतिमाह लगभग 1200 करोड़ से अधिक का सुरक्षित डिजिटल लेनदेन बहुत ही सरलता से संपन्न किया जा रहा है और अब तो फ्रांस सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे 15 से अधिक विदेशी राष्ट्र भी हमारी इस स्वदेशी भुगतान तकनीक को अपनाने के लिए पूरी तरह सहमत हो चुके हैं। 1 अक्टूबर 2022 को देश में 5जी दूरसंचार सेवाओं का विधिवत शुभारंभ हुआ जिससे इंटरनेट की गति में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और अब स्वास्थ्य शिक्षा तथा कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का व्यापक उपयोग संभव हो पाया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी जिसका मुख्य लक्ष्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना और युवाओं के लिए रोज़गार के लाखों नए अवसर सृजित करना था। इसी का यह शानदार परिणाम है कि आज देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और मोबाइल फोन निर्यात में भारत ने 1 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आँकड़ा भी पार कर लिया है। परंतु इस तीव्र तकनीकी विकास और बढ़ते औद्योगीकरण के साथ साथ साइबर सुरक्षा से जुड़े नए और भयंकर खतरे भी उत्पन्न हो रहे हैं। हैकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया था जिसमें समय समय पर कई कठोर संशोधन किए गए हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 15 फरवरी 2017 को पीएसएलवी सी 37 रॉकेट की मदद से एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का सफल अवतरण तो संपूर्ण विश्व ने देखा ही है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की विकराल होती समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्ण रूप से शून्य करने का महत्त्वाकांक्षी